(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचाने गये और मुक्त किये गये	पुनर्वासित
आन्ध्र प्रदेश	36, 289	29,553
बिहार	12,986	12,270
कर्नाटक	62,708	55,231
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,808
राजस्थान	7,478	6,217
तमिलनाडु	38,886	39,375
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल	2,51,424	2,30,915

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बेरोजगारी को समाप्त किया जाना

2519. श्री राम जेठमलानी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा क्या रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु भी कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष सृजित किये जाने वाले सम्भावित रोजगार अवसरों का आवश्यक प्रतिशत कितना-कितना होगा;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के अंतर्गत रोजगार के किन अवसरों को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है, उनका अनुमानित प्रतिशत कितना-कितना है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सन् 2002 तक औसतन 8.5 मिलियन प्रतिवर्ष अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करके लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक मध्यवर्गीय रोजगार नीति तैयार की गई है। रोजगार वृद्धि की नीति की नौवीं योजना में भी जारी रहने की संभावना है तथा 1997-2002 की अवधि के दौरान औसतन 9.5 मिलियन प्रतिवर्ष अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की सम्भावना है। रोजगार वृद्धि की इस दर को प्राप्त करने हेतु इस योजना में उच्च घनत्व रोजगार वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों यथा, कृषि, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण संघटक, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, औपचारिक शहरी क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र, की वृद्धि पर बल देते हुए रोजगार नीति की परिकल्पना की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले से चल रही योजनाओं जैसे आई आर डी पी, जे आर वाई, तथा एन आर वाई के अतिरिक्त नई रोजगार योजनायें यथा, रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा के वी आई सी की 2 मिलियन रोजगार वाली योजना आरंभ की गई है। जनसंख्या के गरीब तबके के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के साथ प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम भी रोजगार सृजन का एक घटक है।

(घ) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 1/79, अनुपत्र संख्या 55]

Import of Cardamom

2520. SHRI JOY NANDUKKARA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of cardamom imported to India during the year 1996-97 so far;

(b) the reasons for allowing import of cardamom when there is strong objection to the import thereof from cardamom growers within the country; and

(c) the names of the countries from which cardamom was imported during the years 1993-94, 1994-95 1995-% and on date in 1996-97?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) During 1996-97 (April-August, 1996), 486

MTs of Large Cardamom valued at Rs. 1.99 crores was imported from Nepal. There were no imports of small cardamom during this period.

(b) Cardamom being a consumer item, its import is permitted against a specific license for export production. However, under the Indo-Nepal treaty of trade, import of goods of Nepalese origin including large cardamom is freely permitted.

(c) The countries from which cardamom was imported are as under:

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (April-Aug.96)
Large Cardamom	Nepal	Bhutan Nepal UAE	Bangladesh Bhutan Nepal Pakistan	Nepal
Small Cardamom	Gautemala Singapore	Gautemala Singapore	Bhutan Singapore	—

(Source: DGCI&S, CALCUTTA)

Report on Child Labour by an NGO to the European Parliament

2521. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether an NGO called "Human Rights Watch" submitted a report to the Europen Parliament accusing Indians of employing child labour;

(b) whether Government are aware that these reports are fabricated and instigated by the intemation vested interests; and

(c) whether Government are aware that bogey of child labour is being used against the developing nations by the multi-national Companies, especially after the WTO came into existence?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Book-Banks for SC/ST/OBC Students in Bihar

2522. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Government have set up Book-Banks for SC/ST/OBC students in the state of Bihar with the co-operation of the State Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of such Book Banks located in the State;

(d) whether Government propose to increase their number in the, State; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes Sir, under the Centrally Sponsored Scheme of Book Banks for SC/ST, Ministry of Welfare and the State Government of Bihar are funding Book Banks in the State of Bihar in the ratio of 50:50 i.e. give their matching share to meet the expenditure for the Book Banks set up for Professional courses for Agriculture, Engineering, Medical (including Indian system of Medicine), Polytechnics and Veterinary courses. There are no Book Banks for the OBC.

(b) and (c) .89, Details are given in the enclosed Statement. *(See* below)

(d) Yes Sir.

(e) Does not arise.